



हरियाणा सरकार

अनुपूरक अनुमान

2023—24

(तीसरी किस्त)

(राज्यपाल के आदेशानुसार हरियाणा विधान सभा को
यथा—प्रस्तुत)

प्रस्तावना

इस खंड में सम्मिलित अनुपूरक मांगे चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक मांगों की तीसरी किस्त है। इस खंड में अनुपूरक विनियोजन चालू वर्ष के दौरान मार्च में 2023 वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान राज्य विधान सभा के सम्मुख रखने के पश्चात उत्पन्न तत्कालिक खर्च को पूरा करने हेतु बजट अनुमान वित्त वर्ष 2023-24 द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि की आवश्यकता के कारण सम्मिलित किए गए हैं। राज्य विधान सभा के समक्ष पहली व दूसरी अनुपूरक मांगें क्रमशः अगस्त, 2023 और दिसम्बर, 2023 में प्रस्तुत की गई थी।

2. इस खंड में सम्मिलित कुल अतिरिक्त मांगे 4771.27 करोड़ रुपये की है, जिसमें से 2132.27 करोड़ रुपये राजस्व परिव्यय तथा 2639.00 करोड़ रुपये पूंजीगत परिव्यय से संबंधित है। इसमें 2639.00 करोड़ रुपये अर्थोपाय अग्रिम भी सम्मिलित है।

3. राज्य की तरलता की स्थिति के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) और अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) को दैनिक आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है। इसलिए राज्य के खजाने पर एसडीएफ और डब्ल्यूएमए का शुद्ध प्रभाव शून्य है।

4. राज्य के खजाने पर पड़ने वाले 2132.27 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ अतिरिक्त राजस्व संसाधनों तथा गैर-उत्पादक व्यय को कम करके पूरा किया जाएगा।

अनुराग रस्तोगी
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तीसरी किस्त)

(राशि रुपये में)

मांग संख्या	विभाग और सेवाए	राजस्व				पूंजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)										1-3
		2014-न्याय प्रशासन	...	22,22,00,000	22,22,00,000		22,22,00,000	
		कुल	...	22,22,00,000	22,22,00,000		22,22,00,000	
06	वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी										4-9
		2049-ब्याज अदायगियाँ	...	1000,00,00,000	1000,00,00,000		1000,00,00,000	
		2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	1,00,000	...	1,00,000		1,00,000	
		2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1110,03,32,000	...	1110,03,32,000		1110,03,32,000	
		कुल	1110,04,32,000	1000,00,00,000	2110,04,32,000		2110,04,32,000	
08	लोक ऋण										10-12
			6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	...	2639,00,00,000	2639,00,00,000	2639,00,00,000	
			कुल	...	2639,00,00,000	2639,00,00,000	2639,00,00,000	

अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तीसरी किस्त)

(राशि रुपयो मे)

मांग संख्या	विभाग और सेवाए	राजस्व				पूंजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च/ तकनीकी/ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल विकास	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,00,000	...	1,00,000		1,00,000	13-15
		कुल	1,00,000	...	1,00,000		1,00,000	
		कुल जोड़	1110,05,32,000	1022,22,00,000	2132,27,32,000	कुल जोड़	...	2639,00,00,000	2639,00,00,000	4771,27,32,000	

मांग संख्या 05
गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक
सुरक्षा/जेल (कारागार)/
न्याय प्रशासन (उच्च
न्यायालय/अभियोजन/एजी
ओटी/कानूनी सेवा
प्राधिकरण)

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (V) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: सात हजार आठ सौ बीस करोड़ तेरह लाख उनतीस हजार रुपये

प्रभारित: दो सौ सैंतीस करोड़ पंचानबे लाख पंचानबे हजार नौ सौ अठानबे रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: पाँच सौ उनासी करोड़ पचास लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (तीसरी किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2014-न्याय प्रशासन

राजस्व

प्रभारित बाईस करोड़ बाईस लाख रुपये ।

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2014-न्याय प्रशासन

51-लागू नहीं

102-उच्च न्यायालय

99-न्यायाधीश

51-लागू नहीं

राजस्व

प्रभारित

(01) वेतन	22,22,00,000
कुल	22,22,00,000
कुल 2014-न्याय प्रशासन	22,22,00,000

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम और दूसरी किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान
2023-24

₹

राजस्व	
स्वीकृत	7820,14,29,000
प्रभारित	237,95,95,998
पूँजीगत	
स्वीकृत	579,52,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि

₹

22,22,00,000

राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	22,22,00,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-

₹

8659,84,24,998

राजस्व	
स्वीकृत	7820,14,29,000
प्रभारित	260,17,95,998
पूँजीगत	
स्वीकृत	579,52,00,000
प्रभारित	...

2014-न्याय प्रशासन**51-लागू नहीं****102-उच्च न्यायालय****99-न्यायाधीश****51-लागू नहीं****प्रभारित****22,22,00,000**

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अन्य अमले के वेतन के खर्चों को वहन करने के लिये 22,25,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका । मांग संख्या 5 के अंतर्गत उपलब्ध बचत को समायोजित करने के उपरांत 22,22,00,000/- रुपये की राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तीसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक "प्रभारित" (राजस्व) खर्च की मद है ।

मांग संख्या 06
वित्त तथा संस्थागत वित्त और
ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं
निपटान/आयोजना तथा
सांख्यिकी

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (VI-VII) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: तेरह हजार छह सौ छिहत्तर करोड़ नवासी लाख चौदह हजार दो सौ रुपये

प्रभारित: इक्कीस हजार दो सौ उनचास करोड़ नब्बे लाख तीस हजार रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: तीन सौ सत्रह करोड़ बत्तीस लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (तीसरी किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2049-ब्याज अदायगियाँ

राजस्व

प्रभारित एक हजार करोड़ रुपये

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन

राजस्व

स्वीकृत एक लाख रुपये

2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

राजस्व

स्वीकृत एक हजार एक सौ दस करोड़ तीन लाख बत्तीस हजार रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2049-ब्याज अदायगियाँ

01-आंतरिक ऋण पर ब्याज

101-बाजार कर्जों पर ब्याज

99-ब्याज सहित बाजारी कर्ज पर ब्याज	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
प्रभारित	
(25) व्याज	890,00,00,000
कुल	890,00,00,000
2049-ब्याज अदायगियाँ	
03-अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज	
104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज	
99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
प्रभारित	
(25) व्याज	110,00,00,000
कुल	110,00,00,000
कुल 2049-ब्याज अदायगियाँ	1000,00,00,000
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	
51-लागू नहीं	
001-दिशा एवं प्रशासन	
99-राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(01) वेतन	5,000
(02) मजदूरी	5,000
(03) मँहगाई भत्ता	5,000
(04) यात्रा खर्चे	5,000
(05) कार्यालय खर्चे	5,000
(06) किराया दरें तथा कर	5,000
(13) सत्कार मनोरंजन खर्चे	5,000

(45) पी.ओ.एल.	5,000
(49) त्योहार अग्रिम	5,000
(66) निपूर्णता तथा विशेष सेवायें	5,000
(67) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5,000
(69) अनुबंधित सेवा	5,000
(70) एल.टी.सी.	5,000
(75) वाहन भत्ता	5,000
(81) कोर्ट फीस	5,000
(84) वकीलों की फीस	5,000
(86) प्रशिक्षण	5,000
(87) मानदेय	5,000
(88) संगणना (सूचना प्रौद्योगिकी)	5,000
(92) ऊर्जा प्रभार	5,000
कुल	1,00,000
कुल 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	1,00,000
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
01-सिविल	
101-अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते	
51-लागू नहीं	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(27) पेंशन	785,03,32,000
कुल	785,03,32,000
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
01-सिविल	
117-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान	
99-सरकार का पेंशन स्कीम हेतु अंशदान	
99-सरकार का पेंशन स्कीम हेतु अंशदान	
राजस्व	₹
स्वीकृत	

(10) अंशदान	325,00,00,000
कुल	325,00,00,000
कुल 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1110,03,32,000

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम और दूसरी किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24 ₹

राजस्व	
स्वीकृत	13830,63,97,065
प्रभारित	21249,90,30,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	467,32,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि ₹

	2110,04,32,000
राजस्व	
स्वीकृत	1110,04,32,000
प्रभारित	1000,00,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- ₹

	37657,90,59,065
राजस्व	
स्वीकृत	14940,68,29,065
प्रभारित	22249,90,30,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	467,32,00,000
प्रभारित	...

2049-ब्याज अदायगियाँ

01-आंतरिक ऋण पर ब्याज

101-बाजार कर्जों पर ब्याज

99-ब्याज सहित बाजारी कर्ज पर ब्याज

51-लागू नहीं

प्रभारित

890,00,00,000

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ब्याज भुगतान पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए 890,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तीसरी किस्त) के माध्यम से 890,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही है।

यह पूंजीगत "प्रभारित" व्यय की एक मद है।

2049-ब्याज अदायगियाँ

03-अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज

104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज

99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज

51-लागू नहीं

प्रभारित

110,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जीपीएफ पर बुक एडजस्टमेंट ब्याज देनदारी को पूरा करने के लिए 110,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तीसरी किस्त) के माध्यम से 110,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही है।

यह पूंजीगत "प्रभारित" व्यय की एक मद है।

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन

51-लागू नहीं

001-दिशा एवं प्रशासन

99-राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,00,000

यह एक नई राज्य स्कीम है वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवनिर्मित "राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय के खर्चों को वहन करने के लिए 99,20,000 रुपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2023-24 में उपबंध नहीं किया जा सका। मांग संख्या 6 में उपलब्ध बचत में से 98,20,000/- रुपये की राशि को समायोजित करने के उपरांत 1,00,000/- की सांकेतिक मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तीसरी किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

01-सिविल

101-अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते

51-लागू नहीं

51-लागू नहीं

स्वीकृत

785,03,32,000

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की राशि के खर्च को वहन करने के लिए 931,34,32,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। 146,31,00,000/- रुपये की धनराशि को मांग संख्या-6 के अंतर्गत स्कीम 01-06-4059-01-051-60-51-वित्त भवन का निर्माण, स्कीम-01-06-5475-51-115-99-51-जिला योजना का सुदृढीकरण और स्कीम-01-06-5475-51-789-99-51-जिला योजना स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के कल्याण में उपलब्ध मौजूदा निधियों से पुनर्विनियोजन के माध्यम से वहन किया जाएगा। इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 785,03,32,000/- रुपये की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2023-24 में उपबंध नहीं किया जा सका। अतः 785,03,32,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तीसरी किश्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

01-सिविल

117-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान

99-सरकार का पेंशन स्कीम हेतु अंशदान

99-सरकार का पेंशन स्कीम हेतु अंशदान

स्वीकृत

325,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय पेंशन योजना में राज्य सरकार के मासिक हिस्सेदारी में बढ़ोतरी के खर्च को वहन करने के लिए 325,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2023-24 में उपबंध नहीं किया जा सका। अतः 325,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तीसरी किश्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

मांग संख्या 08

लोक ऋण

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XXIII-XXV) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत:

प्रभारित:

पूँजीगत

स्वीकृत:

प्रभारित: पचपन हजार दो सौ बीस करोड़ सैंतीस लाख अठारह हजार एक सौ सत्तासी रुपये

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (तीसरी किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

पूँजीगत

प्रभारित दो हजार छः सौ उनतालीस करोड़ रूपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

51-लागू नहीं

110-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम

51-लागू नहीं

51-लागू नहीं

पूँजीगत

₹

प्रभारित

(23) कर्ज

2639,00,00,000

कुल

2639,00,00,000

कुल 6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

2639,00,00,000

4. कुल मूल अनुदान 2023-24 ₹

राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	55220,37,18,187

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि ₹

2639,00,00,000

राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	2639,00,00,000

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- ₹

57859,37,18,187

राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	57859,37,18,187

6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

51-लागू नहीं

110-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम

51-लागू नहीं

51-लागू नहीं

प्रभारित**2639,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वेज एंड मीन्स एडवांस में अल्पकालिक नकद बेमेल पुनर्भुगतान को पूरा करने के लिए 2639,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर विकास होने के कारण बजट 2023-24 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तीसरी किस्त) के माध्यम से 2639,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "प्रभारित" व्यय की एक मद है।

मांग संख्या 12
शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक
)/उच्च शिक्षा (उच्च/
तकनीकी/ विज्ञान तथा
प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल
विकास

वर्ष 2023-24 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XII-XIII) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: इक्कीस हजार एक सौ ग्यारह करोड़ बासठ लाख सत्तानवे हजार रूपये

प्रभारित:

पूंजीगत

स्वीकृत: पांच सौ अड़सठ करोड़

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष (तीसरी किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

राजस्व

स्वीकृत एक लाख रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

102-बाल कल्याण

65-हरियाणा राज्य क्रेच योजना

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(05) कार्यालय खर्चे

10,000

(06) किराया दरें तथा कर	10,000
(34) अन्य प्रभार	5,000
(56) आहार और कैश डोल	5,000
(86) प्रशिक्षण	10,000
(87) मानदेय	50,000
(89) विविध	10,000
कुल	1,00,000
कुल 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,00,000

4. अनुपूरक अनुमान (प्रथम और दूसरी किस्त) जोड़ने के बाद कुल मूल अनुदान 2023-24 ₹

राजस्व	
स्वीकृत	21308,60,17,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	2365,49,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि ₹

	1,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	1,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- ₹

	23674,10,17,000
राजस्व	
स्वीकृत	21308,61,17,000

प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	2365,49,00,000
प्रभारित	...

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

102-बाल कल्याण

65-हरियाणा राज्य क्रेच योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत **1,00,000**

यह एक नई राज्य योजना है। इस स्कीम में हरियाणा राज्य क्रेच नीति-2022 को कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 4,99,85,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत उपलब्ध बचत को समायोजित करने के बाद इस स्कीम एक नई योजना के रूप में कार्यान्वयन करने के लिए 1,00,000/- रुपये की राशि की सांकेतिक मांग अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2023-24 में इसके लिए उपबंध नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/- रुपये की मांग अनुपूरक अनुमान 2023-24 (तृतीय किश्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक "स्वीकृत" (राजस्व) खर्च की मद है।



Government of Haryana

Supplementary Estimates

2023-24

(Third Installment)

**(As presented to the Haryana Vidhan Sabha
by the Order of Governor)**

PREFACE

The Supplementary Demands included in this volume constitute the Third installment of Supplementary Estimates for the current financial year 2023-24. The proposed Third Supplementary appropriations are on account of additionalities required over and above the Budget Grant for the year 2023-24 to meet urgent expenditure which arose after the Budget Estimates 2023-24 passed by the State Legislature in March, 2023. First and Second Supplementary Estimates were placed before the State Legislature in August, 2023 and December, 2023 respectively.

2. The total proposed Third Supplementary Demands are of the order of ₹4771.27 crore, which constitute Revenue expenditure of ₹2132.27 crore and Capital expenditure of ₹2639.00 crore. This includes Ways & Means Advances of the ₹2639.00 core.

3. The Special Drawing Facility (SDF) and Ways & Means Advance (WMA) are being adjusted automatically on day to day basis by Reserve Bank of India depending upon the liquidity position of the State. Hence the net impact of SDF and WMA on State Treasury is zero.

4. The net additional burden of ₹2132.27 crore on the State Exchequer will be met by additional resources mobilization and reducing non-productive expenditure.

Anurag Rastogi
Additional Chief Secretary to Government Haryana
Finance Department

Supplementary Estimates 2023-24 (3rd Installment)

(Amount in ₹)

No of Demand	Department / Services	Revenue				Capital				Grand Total	Reference to pages of details
		MajorHead	Voted	Charged	Total	MajorHead	Voted	Charged	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Home (Home Guard & Civil Defence) /Jails (Prisons)/Administration of Justice (High Court/Prosecution/AGOT/Legal Services Authority)										1-2
		2014-Administration of Justice	...	22,22,00,000	22,22,00,000		22,22,00,000	
		Total	...	22,22,00,000	22,22,00,000		22,22,00,000	
06	Finance and Institutional Finance & Credit Control/Supplies & Disposals/Planning and Statistics (DESA)										3-8
		2049-Interest Payments	...	1000,00,00,000	1000,00,00,000		1000,00,00,000	
		2054-Treasury and Accounts Administration	1,00,000	...	1,00,000		1,00,000	
		2071-Pensions and other Retirement Benefits	1110,03,32,000	...	1110,03,32,000		1110,03,32,000	
		Total	1110,04,32,000	1000,00,00,000	2110,04,32,000		2110,04,32,000	
08	Public Debt		6003-Internal Debt of the State Government	...	2639,00,00,000	2639,00,00,000	2639,00,00,000	9-10

Supplementary Estimates 2023-24 (3rd Installment)

(Amount in ₹)

No of Demand	Department / Services	Revenue				Capital				Grand Total	Reference to pages of details
		MajorHead	Voted	Charged	Total	MajorHead	Voted	Charged	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Total	...	2639,00,00,000	2639,00,00,000	2639,00,00,000	
12	Education (Secondary/Elementary)/Higher Education (Higher, Technical, Science & Technology)/ Women and Child Development										11-13
		2235-Social Security and Welfare	1,00,000	...	1,00,000		1,00,000	
		Total	1,00,000	...	1,00,000		1,00,000	
		Grand-Total	1110,05,32,000	1022,22,00,000	2132,27,32,000	Grand-Total	...	2639,00,00,000	2639,00,00,000	4771,27,32,000	

**Demand No.05
Home (Home Guard & Civil
Defence) /Jails
(Prisons)/Administration of
Justice (High
Court/Prosecution/AGOT/Lega
I Services Authority)**

See page V of Statement of Demands for Grants and Appropriation for the year 2023-24

1.Original Grant

Revenue

Voted Rupees Seven Thousand Eight Hundred Twenty Crore Thirteen Lac Twenty Nine Thousand

Charged Rupees Two Hundred Thirty Seven Crore Ninety Five Lac Ninety Five Thousand Nine Hundred Ninety Eight

Capital

Voted Rupees Five Hundred Seventy Nine Crore Fifty Lac

Charged

2. SUPPLEMENTARY ESTIMATES of the amount required in the year ending (3rd Instalment) 31 March, 2024 to defray charges in respect of :-

2014-Administration of Justice

Revenue

Charged Rupees Twenty Two Crore Twenty Two Lakh

3. SUB/MINOR HEADS under which the supplementary grant will be accounted for :-

2014-Administration of Justice

51-N.A.

102-High Court

99-Judges.

51-N.A.

Revenue

₹

Charged

(01) Salary

22,22,00,000

Total

22,22,00,000

Total 2014-Administration of Justice

22,22,00,000

4.Total Original Estimates after adding Supplementary Estimates (1st & 2nd Instalment 2023-24)

₹

Revenue

Voted	7820,14,29,000
Charged	237,95,95,998
Capital	
Voted	579,52,00,000
Charged	0
5. Add sum now required:	₹
	22,22,00,000
Revenue	
Voted	0
Charged	22,22,00,000
Capital	
Voted	0
Charged	0
6. Total Estimates after adding the sum now required	₹
	8659,84,24,998
Revenue	
Voted	7820,14,29,000
Charged	260,17,95,998
Capital	
Voted	579,52,00,000
Charged	0
2014-Administration of Justice	
51-N.A.	
102-High Court	
99-Judges.	
51-N.A.	
	₹
Charged	22,22,00,000

An additional amount of Rs. 22,25,00,000/- is required to meet out the expenditure on account of Salary of Judges & other staff of Hon'ble High Court during the financial year 2023-24.

Being a post budget development, the provision could not be made in the Budget Estimates 2023-24. After adjusting the available saving within the Demand No. 5, an amount of Rs. 22,22,00,000/- is being made through Supplementary Estimates 2023-24 (3rd Instalment).

This is an item of "Charged" (Revenue) expenditure.

**Demand No.06
Finance and Institutional
Finance & Credit
Control/Supplies &
Disposals/Planning and
Statistics (DESA)**

See page VI-VII of Statement of Demands for Grants and Appropriation for the year 2023-24

1.Original Grant

Revenue

Voted Rupees Thirteen Thousand Six Hundred Seventy Six Crore Eighty Nine Lac
Fourteen Thousand Two Hundred

Charged Rupees Twenty One Thousand Two Hundred Forty Nine Crore Ninety Lac
Thirty Thousand

Capital

Voted Rupees Three Hundred Seventeen Crore Thirty Two Lac

Charged

2. SUPPLEMENTARY ESTIMATES of the amount required in the year ending (3rd Instalment) 31 March, 2024 to defray charges in respect of :-

2049-Interest Payments

Revenue

Charged Rupees One Thousand Crore

2054-Treasury and Accounts Administration

Revenue

Voted Rupees One Lakh

2071-Pensions and other Retirement Benefits

Revenue

Voted Rupees One Thousand One Hundred Ten Crore Three Lakh Thirty Two
Thousand only.

3. SUB/MINOR HEADS under which the supplementary grant will be accounted for :-

2049-Interest Payments

01-Interest on Internal Debt

101-Interest on market loans

99-Interest on Market loans bearing Interest

51-N.A.

Revenue	₹
Charged	
(25) Interest	890,00,00,000
Total	890,00,00,000

2049-Interest Payments

03-Interest on Small Savings, Provident Funds etc.

104-Interest on State Provident Funds

99-Interest on State Provident Fund

51-N.A.

Revenue	₹
Charged	
(25) Interest	110,00,00,000
Total	110,00,00,000
Total 2049-Interest Payments	1000,00,00,000

2054-Treasury and Accounts Administration

51-N.A.

001-Direction and Administration

99-Directorate of State Audit

51-NA

Revenue	₹
Voted	
(01) Salary	5,000
(02) Wages	5,000
(03) Dearness Allowances	5,000
(04) Travel Expenses	5,000
(05) Office Expenses	5,000
(06) Rent, Rates and Taxes	5,000
(13) Hospitality/Entertainment Expenses	5,000
(45) P.O.L	5,000
(49) Festival Advances	5,000
(66) Proficiency & Special Services	5,000
(67) Medical Reimbursement	5,000
(69) Contractual Service	5,000
(70) Leave Travel Concession	5,000

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS 2023-24

5

(75) Conveyance Allowance	5,000
(81) Court Fee	5,000
(84) Legal Fee to Counsels	5,000
(86) Training	5,000
(87) Honorarium	5,000
(88) Computerisation (IT)	5,000
(92) Energy Charges	5,000
Total	1,00,000
Total 2054-Treasury and Accounts Administration	1,00,000
2071-Pensions and other Retirement Benefits	
01-Civil	
101-Superannuation and Retirement Allowances	
51-N.A.	
51-N.A.	
Revenue	₹
Voted	
(27) Pensions	785,03,32,000
Total	785,03,32,000
2071-Pensions and other Retirement Benefits	
01-Civil	
117-Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme	
99-Defined Contribution Pension Scheme of Haryana Legislature	
99-Government Contribution to Defined Contributory Pension Scheme	
Revenue	₹
Voted	
(10) Contributions	325,00,00,000
Total	325,00,00,000
Total 2071-Pensions and other Retirement Benefits	1110,03,32,000
4.Total Original Estimates after adding Supplementary Estimates (1st & 2nd Instalment 2023-24)	₹
Revenue	
Voted	13830,63,97,065
Charged	21249,90,30,000

Capital	
Voted	467,32,00,000
Charged	0
5. Add sum now required:	₹
	2110,04,32,000
Revenue	
Voted	1110,04,32,000
Charged	1000,00,00,000
Capital	
Voted	0
Charged	0
6. Total Estimates after adding the sum now required	₹
	37657,90,59,065
Revenue	
Voted	14940,68,29,065
Charged	22249,90,30,000
Capital	
Voted	467,32,00,000
Charged	0
2049-Interest Payments	
01-Interest on Internal Debt	
101-Interest on market loans	
99-Interest on Market loans bearing Interest	
51-N.A.	
	₹
Charged	890,00,00,000
<p>An additional amount of Rs.890,00,00,000/- is required to meet out the expenditure on interest payment during the financial year 2023-24. Being a post Budget development, provision could not be made in Budget 2023-24. Hence, additional demand of Rs.890,00,00,000/- is being made through the Supplementary Estimates 2023-24 (3rd Instalment). This is an item of Revenue "Charged" expenditure.</p>	
2049-Interest Payments	
03-Interest on Small Savings, Provident Funds etc.	
104-Interest on State Provident Funds	
99-Interest on State Provident Fund	

51-N.A.

₹

Charged**110,00,00,000**

An additional amount of Rs.110,00,00,000/- is required to meet out the book adjustment interest liability on GPF during the financial year 2023-24. Being a post Budget development, provision could not be made in Budget 2023-24. Hence, additional demand of Rs.110,00,00,000/- is being made through the Supplementary Estimates 2023-24 (3rd Instalment).

This is an item of Revenue "Charged" expenditure.

2054-Treasury and Accounts Administration

51-N.A.

001-Direction and Administration**99-Directorate of State Audit**

51-NA

₹

Voted**1,00,000**

This is a new state scheme. An additional amount of Rs. 99,20,000/- is required to meet out the expenditure on account of newly created "Directorate of State Audit" during Financial Year 2023-24.

Being a post budget development, the provision could not be made in the Budget Estimates 2023-24. After adjusting the available saving of Rs. 98,20,000/- within the Demand No. 6, a token provision of Rs. 1,00,000/- is being made through Supplementary Estimates 2023-24 (3rd Installment).

This is an item of Revenue "Voted" expenditure.

2071-Pensions and other Retirement Benefits**01-Civil****101-Superannuation and Retirement Allowances**

51-N.A.

51-N.A

₹

Voted**785,03,32,000**

An additional amount of Rs. 931,34,32,000/- is required to meet out the expenditure on account of the payment of superannuation and retirements benefits to the State Government retired employees during the financial year 2023-24. An amount of Rs. 146,31,00,000/- will be met out through re-appropriation from funds available in scheme namely P-01-06-4059-01-051-60-51 -Construction of Vitt Bhawan,, P-01-06-5475-51-115-99-51- Strengthening of District Plan and P-01-06-5475-51-789-99-51-Welfare of scheduled caste under District Plan scheme in the same Demand No. 6. Hence, an amount of Rs. 785,03,32,000/- is required during financial year 2023-24.

Being a post budget development, the provision could not be made in the Budget Estimates 2023-24. Hence, the demand of Rs. 785,03,32,000/- is being made through Supplementary Estimates 2023-24 (3rd Installment).

This is an item of Revenue "Voted" expenditure.

2071-Pensions and other Retirement Benefits**01-Civil****117-Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme**

99-Defined Contribution Pension Scheme of Haryana Legislature**99-Government Contribution to Defined Contributory Pension Scheme**

₹

Voted**325,00,00,000**

An additional amount of Rs. 325,00,00,000/- is required to meet out the expenditure on account of enhancement in the monthly contribution of State Government share in National Pension Scheme (NPS) during the financial year 2023-24.

Being a post budget development, the provision could not be made in the Budget Estimates 2023-24. Hence, the demand of Rs. 325,00,00,000/- is being made through Supplementary Estimates 2023-24 (3rd Installment).

This is an item of Revenue "voted" expenditure.

**Demand No.08
Public Debt**

See page XXIII-XXV of Statement of Demands for Grants and Appropriation for the year 2023-24

1.Original Grant

Revenue

Voted

Charged

Capital

Voted

Charged Rupees Fifty Five Thousand Two Hundred Twenty Crore Thirty Seven Lac Eighteen Thousand One Hundred Eighty Seven

2. SUPPLEMENTARY ESTIMATES of the amount required in the year ending (3rd Instalment) 31 March, 2024 to defray charges in respect of :-

6003-Internal Debt of the State Government

Capital

Charged Rupees Two Thousand Six Hundred Thirty Nine Crore

3. SUB/MINOR HEADS under which the supplementary grant will be accounted for :-

6003-Internal Debt of the State Government

51-N.A.

110-Ways and Means Advances from the Reserve Bank of India

51-N.A

51-N.A

Capital

₹

Charged

(23) Loans

2639,00,00,000

Total

2639,00,00,000

Total 6003-Internal Debt of the State Government

2639,00,00,000

4.Total Original Estimates after adding Supplementary Estimates (1st & 2nd Instalment 2023-24)

₹

Revenue

Voted

0

Charged

0

Capital

Voted	0
Charged	55220,37,18,187
5. Add sum now required:	₹
	2639,00,00,000
Revenue	
Voted	0
Charged	0
Capital	
Voted	0
Charged	2639,00,00,000
6. Total Estimates after adding the sum now required	₹
	57859,37,18,187
Revenue	
Voted	0
Charged	0
Capital	
Voted	0
Charged	57859,37,18,187
6003-Internal Debt of the State Government	
51-N.A.	
110-Ways and Means Advances from the Reserve Bank of India	
51-N.A	
51-N.A	
	₹
Charged	2639,00,00,000

An additional amount of Rs.2639,00,00,000/- is required to meet short term cash mismatch repayment in Ways and Means Advance during the financial year 2023-24. Being a post Budget development, provision could not be made in Budget 2023-24. Hence, additional demand of Rs.2639,00,00,000/-is being made through the Supplementary Estimates 2023-24 (3rd Instalment).
This is an item of Revenue "Charged" expenditure.

**Demand No.12
Education
(Secondary/Elementary)/Higher Education (Higher,
Technical, Science &
Technology)/ Women and
Child Development**

See page XII-XIII of Statement of Demands for Grants and Appropriation for the year 2023-24

1.Original Grant

Revenue

Voted Rupees Twenty One Thousand One Hundred Eleven Crore Sixty Two Lac
Ninety Seven Thousand

Charged

Capital

Voted Rupees Five Hundred Sixty Eight Crore

Charged

2. SUPPLEMENTARY ESTIMATES of the amount required in the year ending (3rd Instalment) 31 March, 2024 to defray charges in respect of :-

2235-Social Security and Welfare

Revenue

Voted Rupees One Lakh

3. SUB/MINOR HEADS under which the supplementary grant will be accounted for :-

2235-Social Security and Welfare

02-Social Welfare

102-Child Welfare

65-Haryana State Creche Scheme

51-NA

Revenue

₹

Voted

(05) Office Expenses	10,000
(06) Rent, Rates and Taxes	10,000
(34) Other Charges	5,000
(56) Feeding and Cash Dole	5,000
(86) Training	10,000
(87) Honorarium	50,000

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS 2023-24

12

(89) Miscellaneous	10,000
Total	1,00,000
Total 2235-Social Security and Welfare	1,00,000
4.Total Original Estimates after adding Supplementary Estimates (1st & 2nd Instalment 2023-24)	₹
Revenue	
Voted	21308,60,17,000
Charged	0
Capital	
Voted	2365,49,00,000
Charged	0
5. Add sum now required:	₹
	1,00,000
Revenue	
Voted	1,00,000
Charged	0
Capital	
Voted	0
Charged	0
6. Total Estimates after adding the sum now required	₹
	23674,10,17,000
Revenue	
Voted	21308,61,17,000
Charged	0
Capital	
Voted	2365,49,00,000
Charged	0
2235-Social Security and Welfare	
02-Social Welfare	
102-Child Welfare	
65-Haryana State Creche Scheme	
51-NA	

₹

Voted**1,00,000**

This is a new State Scheme. An additional amount of Rs. 4,99,85,000/- is required to meet out the expenditure on account of implementation of Haryana State Creche Policy-2022 during the financial year 2023-24. After adjusting the available saving within the Grant No.12 a token amount of Rs. 1,00,000/- is required being a new scheme.

Being a post budget development provision could not be made in the Budget Estimates for year 2023-24. Hence, the demand of Rs. 1,00,000/- is being made through the Supplementary Estimates 2023-24 (3rd instalment).

This is an item of "Voted" (Revenue) Expenditure.